



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2018/चैत्र 20, 1940

No. 129]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2018/CHAITRA 20, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

मामला सं. ओ. आई. 09/2018

विषय : ब्राजील, इंडोनेशिया और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " गैर-प्लास्टिक वाले औद्योगिक ग्रेड नाइट्रोसेलुलोज - एथेनॉल और पानी में डैम्पड को छोड़कर " के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/12/2018-डीजीएडी.—मै. नाइट्रेक्स कैमिकल्स इंडिया (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन (जिसे याचिका भी कहा गया है) दायर किया है जिसमें ब्राजील, इंडोनेशिया और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "गैर-प्लास्टिक वाले औद्योगिक ग्रेड नाइट्रोसेलुलोज - एथेनॉल और पानी में डैम्पड को छोड़कर" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच करने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं। प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद है 'गैर-प्लास्टिकयुक्त औद्योगिक ग्रेड नाइट्रोसेलुलोज, - एथेनॉल और पानी में डैम्पड को छोड़कर, जो 10.7% से 12.2% की सीमा में नाइट्रोजन सामग्री रखता है। विचाराधीन उत्पाद में क्रूरता, स्थायित्व, तेज विलायक रिलीज क्षमता और विलेयता जैसी गुण हैं। विचाराधीन उत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल लुगदी है, यानी सेलूलोज़ जिसे शुद्ध सेलूलोज़ से प्राप्त किया जाता है या तो कपास लिंटर्स या लकड़ी के गूदा के रूप में प्राप्त होता है। विचाराधीन उत्पाद नाइट्रिक एसिड या किसी अन्य शक्तिशाली नाइट्रेटिंग एजेंट के संपर्क में नाइट्रेटिंग सेलूलोज़ द्वारा बनाई जाने वाली एक ज्वलनशील यौगिक है और इसका इस्तेमाल लकड़ी लैकर्स, ऑटो रिफिनिश पेंट्स, चमड़ा फिनिशिंग लैकेजर्स, नाखून वार्निश, प्रिंटिंग इंक आदि में किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को आईटीसी एचएस उपशीर्ष 39122019 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वह उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

5. आवेदकों ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अधीन उन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" हैं।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

6. यह आवेदन मै. नाइट्रेक्स कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

7. आवेदकों का उत्पादन भारत में उत्पादित समान उत्पाद के भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, आवेदकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। अतः आवेदक नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं।

घ. संबद्ध देश

8. वर्तमान जाँच में शामिल देश ब्राजील, इंडोनेशिया और थाईलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) हैं।

ङ सामान्य मूल्य

ब्राजील और थाईलैंड में सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने ब्राजील और थाईलैंड के घरेलू बाजार में विषय वस्तु के बिक्री के वास्तविक लेनदेन मूल्य के संबंध में प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। वास्तविक लेनदेन की कीमतों के प्रमाण प्राप्त करने के प्रयास भी किए गए हैं जिन पर ब्राजील और थाईलैंड में विषय वस्तु बेची जा रही है। हालांकि, आवेदक ब्राजील और थाईलैंड के घरेलू बाजार में विषय वस्तु के मूल्य की कोई जानकारी / प्रमाण प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार, आवेदक ने

ब्राजील और थाईलैंड से ब्राजील और थाईलैंड से निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य पर आधारित ब्राजील और थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है, क्योंकि निर्यातक देश से निर्यात किए जाने वाले लेख की तुलनात्मक प्रतिनिधि कीमत

इंडोनेशिया में सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने दावा किया है कि इंडोनेशिया में घरेलू सामानों की मूल्य वस्तुओं के मूल्य / सूचना के मूल्य / मूल्य सूची के रूप में या इंडोनेशिया में विषय वस्तु के उत्पादक के कोटेशन के लिए जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। हालांकि, आवेदक इंडोनेशिया के घरेलू बाजार में विषय वस्तु की कीमत के किसी भी जानकारी / साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। नीचे बताया गया है, जैसा कि इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन की लागत के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया है।

- i) घरेलू उद्योग के अनुसार प्रमुख कच्चे माल की कीमतें
- ii) चोट की अवधि में घरेलू उद्योग का सर्वश्रेष्ठ खपत मानदंड
- iii) घरेलू उद्योग के अनुसार रूपांतरण लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च
- iv) 5% उचित लाभ मार्जिन

च. निर्यात कीमत

11. आवेदकों द्वारा निर्यात कीमत का दावा डीजीसीआईएस से प्राप्त सौदा वार आयात आकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से भारत आयात कीमत के रूप में किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, बैंक प्रभारों के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

छ. पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत के साथ की गई है जो प्रत्येक संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में भारी पाटन मार्जिन दर्शाती है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

13. आवेदकों ने समग्र रूप से और उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की भारी मात्रा, कीमत कटौती और लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय, नकद प्रवाह पर परिणामी भारी प्रतिकूल प्रभाव तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों और बाजार हिस्से में कमी और लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के निम्न स्तर के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से हुए कथित पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

14. आवेदकों ने इन आधारों पर वास्तविक क्षति के खतरे का दावा भी किया है कि संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि की दर काफी अधिक है, संबद्ध उत्पादकों के पास भारी अतिरिक्त क्षमताएं हैं, कीमत कटौती काफी अधिक है और भारतीय बाजार आकर्षक है जिससे आयातों में और वृद्धि होने की संभावना है और उनसे घरेलू बाजार में ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहे हैं।

झ. जाँच की शुरुआत

15. प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पर्याप्त साक्ष्य हैं इसलिए प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को

निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए एतद्वारा जाँच की शुरुआत करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में जाँच की शुरुआत करते हैं।

ज. जाँच की अवधि (पीओआई)

16. याचिकाकर्ताओं ने अप्रैल 2016 – सितम्बर, 2017 के रूप में जाँच अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित अवधि अप्रैल, 2016 से सितम्बर 2017 तक (18 महीनों) को उचित मानते हैं। क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2013 – मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016 और जाँच अवधि की अवधि शामिल होगी।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें और अपने विचारों से अवगत करा सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001
dgad.india@gov.in

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

ठ. समय-सीमा

19. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
 20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ड. गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

22. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

23. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

त. असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निदिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2018

Case No. O.I. 09/2018

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose excluding Nitrocellulose Damped in Ethanol and Waterwet” originating in or exported from Brazil, Indonesia and Thailand.

F. No. 6/12/2018-DGAD.—M/s. Nitrex Chemicals India Limited (hereinafter referred to as ‘petitioners’ or ‘applicants’) has filed an application (also referred to as petition) along with relevant

information before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of 'Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose excluding Nitrocellulose Damped in Ethanol and Water-wet' (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from Brazil, Indonesia and Thailand (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and 'injury' exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

A. Product under consideration

3. Product under consideration in the present case is 'Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose, excluding Nitrocellulose Damped in Ethanol and Water-wet', having nitrogen content in the range of 10.7% to 12.2%. The product under consideration has properties like toughness, durability, fast solvent release capacity and solubility. The most important raw material of the product under consideration is pulp, i.e. cellulose which is obtained from purified cellulose either in the form of cotton linters or wood pulp. The product under consideration is a flammable compound formed by nitrating cellulose through exposure to nitric acid or another powerful nitrating agent and it is used in the manufacture of Wood Lacquers, Auto Refinish Paints, Leather Finishing Lacquers, Nail Varnishes, Printing Inks etc.

4. Product under consideration is classified under ITC HS Sub-heading 39122019. The Customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

B. Like Article

5. The applicants have claimed that there is no known difference in product produced by the applicants and exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the domestic industry in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Domestic Industry & Standing

6. The application has been filed by M/s Nitrex Chemicals India Limited. The petitioner is the sole producer of the subject goods.

7. The production by the applicants constitutes 'a major proportion' of Indian production of the like product produced in India. Further, the applicants have claimed that they have neither imported the subject goods, nor are they related to any importer or exporter of the subject goods. The applicants, therefore constitutes "domestic industry" within the meaning of Rule 2 (b) and thus satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. Subject Countries

8. The countries involved in the present investigation are Brazil, Indonesia and Thailand (hereinafter referred to as 'Subject Countries').

E. Normal value

Normal Value in Brazil and Thailand

9. Applicant has claimed to have made efforts to get authentic evidence with regard to actual transaction price of sale of the subject goods in the domestic market of Brazil and Thailand. Efforts have been also made to get evidence of the actual transaction prices at which the subject goods are being sold in Brazil and Thailand. However, applicant has not been able to get any information/evidence of price of subject goods in the domestic market of Brazil and Thailand. Thus, the applicant has calculated the Normal value for Brazil and Thailand based on the CIF price of the subject goods exported from Brazil and Thailand to the other countries as comparable representative price of the like article when exported from the exporting country

Normal Value in Indonesia

10. Applicant has claimed to have made efforts to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market in Indonesia in the form of price lists or quotations of producers of subject goods in Indonesia. However, the applicant has not been able to get any information/evidence of price of subject goods in the domestic market of Indonesia. Normal value for Indonesia has been determined on the basis of estimates of cost of production, as explained below.

- a. Major raw material prices as per domestic industry
- b. Best consumption norms of domestic industry in the injury period
- c. Conversion costs, selling, general & administrative expenses as per domestic industry
- d. 5% reasonable profit margin

F. Export Price

11. The export price has been claimed by the applicants as the weighted average import price from the subject countries based on the transaction-wise import data procured from DGCI&S. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges to arrive at the net export price.

G. Dumping Margin

12. The comparison of normal values with the ex-factory export price has been carried out, which shows a significant dumping margin in respect of the subject goods exported by each of the subject countries.

H. Evidence of Injury and Causal Link

13. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production & consumption, price undercutting, and consequent significant adverse impact on profitability, return on capital employed, cash flow, and deterioration in production, capacity utilization, sales and market share of the domestic industry and low level of profits, cash profits & return on investment. There is sufficient prima facie evidence of 'material injury' being suffered by the domestic industry caused by alleged dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

14. The applicants have also claimed threat of material injury on the grounds that rate of increase in imports from the subject countries is significantly high, the subject producers have huge surplus capacities, price undercutting is significant and the Indian market is attractive which is likely to further increase in imports and cause suppressing or depressing effects in the domestic market.

I. Initiation of Investigation

15. The authority finds sufficient *prima facie* evidence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between alleged dumping and injury, to justify initiation of anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry. Accordingly, the authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

J. Period of Investigation (POI)

16. The petitioner has proposed period of investigation as April 2016-September 2017. The Authority considers the proposed period April 2016 – September 2017 (18 months) as appropriate for the purposes of present investigations. The injury investigation period shall cover the periods April 2013 - March 2014, April 2014 - March 2015, April 2015 - March 2016 and the period of investigation.

K. Submission of Information

17. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi -110001.
dgad.india@gov.in

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the authority at www.dgtr.gov.in) within the time limit set out below.

L. Time limit

19. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation

M.Submission of Information on Confidential/ Non-Confidential basis

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

22. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such Information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

27. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

O. Non-cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority